Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

17 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. प्रधानमंत्री ने मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में 71,850 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 सितंबर 2025 तक पांच राज्यों का दौरा किया और बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, रेलवे, कृषि, संस्कृति और रक्षा में 71,850 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

- **मिजोरम में उन्होंने 8,070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया, तीन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और खेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया।**

- **मणिपुर में उन्होंने चुराचांदपुर में सड़कों और राजमार्गों सहित 7,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा इम्फाल में सिविल सचिवालय और इमा मार्केट जैसी 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।**

- **असम में उन्होंने 13 सितंबर को भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती में भाग लिया और 14 सितंबर को गुवाहाटी रिंग रोड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्रों सहित 18,530 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।**

Key Points:-

(i) 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल में, उन्होंने रक्षा मंत्रालय (राजनाथ सिंह) के तहत कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन-2025 का उद्घाटन किया, जिसमें सशस्त्र बलों में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(ii) बिहार में उन्होंने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, 25,000 करोड़ रुपये के पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट, कोसी-मेची लिंक परियोजना और प्रमुख रेल लाइनों सहित 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

(iii) उन्होंने कृषि मंत्रालय (शिवराज सिंह चौहान) के तहत बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया, जिससे मखाना की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात और किसानों की आय को बढ़ावा मिला क्योंकि बिहार भारत के कुल मखाना का 90% उत्पादन करता है।

2. प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और बिहार में 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

15 सितंबर 2025 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और बिजली, रेल, सिंचाई, कृषि, आवास और कनेक्टिविटी को कवर करते हुए 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

• इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी उपस्थित थे।

• सबसे बड़ी परियोजना भागलपुर में 3×800 मेगावाट की पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट थी, जिसकी लागत 25,000 करोड़ रुपये थी, जो बिहार के बिजली क्षेत्र में सबसे बड़ा निजी निवेश था।

• 2,680 करोड़ रुपये की लागत वाली कोसी-मेची अंतर-राज्यीय नदी लिंक परियोजना (चरण-1) की आधारशिला रखी गई, जिससे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा तथा जल निकासी क्षमता 20,000 क्यूसेक तक बढ़ जाएगी।

Key Points:-

(i) प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में बिक्रमशिला-कटारिया लाइन (2,170 करोड़ रुपये), अररिया-गलगलिया लाइन का उद्घाटन (4,410 करोड़ रुपये) और वंदे भारत एक्सप्रेस (जोगबनी-दानापुर) और अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना शामिल है।

(ii) सरकार ने बिहार के मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी घोषणा की, जो भारत के कुल उत्पादन का 90% है।

(iii) सामाजिक योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और PMAY-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत आवास के साथ-साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण निधि शामिल है।

3. प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में 8,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

13 सितंबर 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के इम्फाल और चुराचांदपुर का दौरा किया और 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएँ बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, डिजिटल विकास और महिला सशक्तिकरण को कवर करती हैं, जो मणिपुर के विकास और कल्याण को एक बड़ा बढ़ावा देंगी।

• इम्फाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें 538 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सिविल सचिवालय और लगभग 101 करोड़ रुपये की लागत से विकसित नया मणिपुर पुलिस मुख्यालय शामिल है।

• प्रधानमंत्री ने इम्फाल के मंत्रिपुखरी में 114 करोड़ रुपये की लागत से विकसित सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का भी उद्घाटन किया।

• महिला सशक्तिकरण के एक हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी ने टेंग्नौपाल, नोनी, पल्लेल और मोइरांग जिलों में 24 करोड़ रुपये की लागत से नए "इमा" (माताओं) बाजारों का उद्घाटन किया, ताकि स्थानीय और पारंपरिक व्यवसायों में लगी महिला

उद्यमियों, व्यापारियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को एक मजबूत मंच प्रदान किया जा सके।

Key Points:-

(i) इम्फाल पश्चिम में, उन्होंने 13 करोड़ रुपये की लागत से विकसित लीशांग हिडेन सांस्कृतिक एवं विरासत पार्क का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य पर्यटन और शैक्षिक संवर्धन के लिए मणिपुर की सांस्कृतिक विविधता, स्वदेशी विरासत और स्थानीय परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

(ii) चुराचांदपुर में, प्रधानमंत्री मोदी ने 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें 3,647 करोड़ रुपये की मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना के साथ-साथ 2,500 करोड़ रुपये की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे सड़क संपर्क और शहरी बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

(iii) चुराचांदपुर में अन्य प्रमुख लॉन्चों में 550 करोड़ रुपये की लागत वाली मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना शामिल है, जो डिजिटल सशक्तिकरण और IT आधारित सेवाओं पर केंद्रित है, और 142 करोड़ रुपये की लागत से नौ स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावास, जो राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा, आवास और रोजगार भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

4. सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की।

केंद्र सरकार ने (12-13 सितंबर 2025) फसल वर्ष 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक) के लिए अफीम की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति का अनावरण किया, पात्र किसानों का विस्तार किया और वित्त मंत्रालय के तहत प्रमुख राज्यों में उपज और गुणवत्ता नियंत्रण को कड़ा किया।

- **यह नीति तीन पारंपरिक अफीम उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर लागू होती है, तथा लाइसेंस के लिए पात्र किसानों की संख्या में लगभग 23.5% की वृद्धि करती है, जिससे कुल संख्या पिछले फसल वर्ष के लगभग 1.06 लाख से बढ़कर लगभग 1.21 लाख (अर्थात ~121,000) हो जाती है।**

- **नई नीति के तहत, जिन किसानों ने पहले 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक अफीम भूसे की उपज प्राप्त की है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें अफीम गोंद की खेती की पारंपरिक विधि को अपनाने का विकल्प भी शामिल है, जिससे आम तौर पर अधिक लाभ मिलता है और चिकित्सा उपयोग के लिए इसकी मांग भी अधिक है।**

- **नीति में कड़े प्रदर्शन मानक भी शामिल किए गए हैं: CPS योजना (कंसंट्रेटेड पोस्ता स्ट्रॉ) के तहत जो किसान पिछले वर्ष (2024-25) में 800 किलोग्राम/हेक्टेयर की न्यूनतम योग्यता उपज (MQY) को पूरा करने में विफल रहे, उनके लाइसेंस 2025-26 में निलंबित कर दिए जाएंगे।**

Key Points:-

(i) लाइसेंसिंग को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत प्रशासित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की निगरानी होती है, और इसे औषधीय और उपशामक देखभाल के लिए एल्कलॉइड (जैसे मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अफीम और अल्कलॉइड कारखानों (GOAF) के साथ जोड़ा जाता है।

(ii) गुणवत्ता और आधुनिक मानकों का समर्थन करने के लिए, सरकार "उच्च प्रदर्शन करने वाले" किसानों के लिए प्रोत्साहन, प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और यह सुनिश्चित करने पर जोर देती है कि मध्य प्रदेश के नीमच में सरकारी अल्कलॉइड फैक्ट्री जैसी संस्थाएं डब्ल्यूएचओ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) प्रमाणन बनाए रखें।

(iii) उपज और लाइसेंसिंग में बदलावों के अलावा, लगभग 1995-96 से ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि किसानों के प्रदर्शन, पात्रता पर नज़र रखी जा सके और कृषि भूमि के दुरुपयोग या अन्य उपयोग को रोका जा सके; इसका उद्देश्य मानदंडों को पूरा करने वाले सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाना है। सरकार ने उन विशिष्ट क्षेत्रों (क्षेत्रों) को भी अधिसूचित करना जारी रखा है जहाँ खेती की अनुमति है।

5. पारदर्शिता और सैन्य तैयारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद मैनुअल (DPM) 2025 को मंजूरी दी गई।

14 सितंबर 2025 को, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय (MoD) में राजस्व खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए 2009 के संस्करण के स्थान पर रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 को मंज़ूरी दे दी। यह नया नियमावली स्वदेशीकरण, पारदर्शिता, तेज़ निर्णय लेने और MSMEs, स्टार्टअप्स और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSU) की मज़बूत भागीदारी पर ज़ोर देता है।

- **DPM 2025 वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की राजस्व खरीद को नियंत्रित करेगा और इसका उद्देश्य खरीद में देरी और लागत वृद्धि को कम करते हुए भारतीय सेना (IA), भारतीय नौसेना (IN) और भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन तत्परता को मजबूत करना है।**

- **नीति में तरल क्षति (LD) को घटाकर 0.1% करने, LD सीमा को 5% तक सीमित करने और प्रोटोटाइप विकास को दंड से छूट देने जैसी छूटें शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्तिकर्ताओं को पाँच वर्षों तक गारंटीकृत ऑर्डर प्राप्त हो सकें, जिन्हें विशेष मामलों में 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।**

- **यह स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और स्वदेशीकरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और शिक्षाविदों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करके नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देता है।**

Key Points:-

(i) पारदर्शिता में सुधार के लिए, DPM 2025 डिजिटल खरीद प्रणाली को अनिवार्य बनाता है, रक्षा PSU से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOCs) की आवश्यकता को समाप्त करता है, और सीमित निविदा को 50 लाख रुपये तक सीमित करता है, जिससे एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

(ii) यह मैनुअल जटिल हथियार प्रणालियों के लिए विकास प्रावधानों, तत्काल मरम्मत के लिए 15% लागत वृद्धि भत्ते, और महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए सरकार-से-सरकार (G2G) उच्च-मूल्य की खरीद को सरल बनाने के साथ सैन्य तैयारियों को भी मजबूत करता है।

(iii) आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखित, DPM 2025 घरेलू उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है, साथ ही साथ तीनों रक्षा सेवाओं में संयुक्तता और तालमेल को बढ़ावा मिलता है।

INTERNATIONAL

1. अल्बानिया ने विश्व के पहले AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की।

सितंबर 2025 में, अल्बानिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली, डिएला को सार्वजनिक खरीद मंत्री नियुक्त करने वाला पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री एडी रामा ने 11 सितंबर 2025 को तिराना में उनका परिचय कराया, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार से लड़ना और सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

- **डिएला, जिसका अर्थ अल्बानियाई में "सूर्य" है, को पहली बार जनवरी 2025 में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना सोसायटी एजेंसी (AKSHI) के तहत ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था।**

- **मंत्री पद पर नियुक्ति से पहले उन्होंने 36,600 से अधिक दस्तावेजों का प्रसंस्करण किया तथा 95% सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया।**

- **उनकी नई भूमिका में सार्वजनिक खरीद निविदाओं का प्रबंधन शामिल है, जिसका लक्ष्य 100% भ्रष्टाचार-मुक्त प्रणाली बनाना है। यह कदम मई 2025 के चुनावों के बाद उठाया गया है, जहाँ सोशलिस्ट पार्टी ने चौथा कार्यकाल हासिल किया है, जिससे अल्बानिया की यूरोपीय संघ में शामिल होने की महत्वाकांक्षाएँ और मज़बूत हुई हैं।**

Key Points:-

(i) पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में प्रस्तुत डिएला का अवतार पारदर्शिता का प्रतीक है, लेकिन चूँकि वह मानव नहीं है, इसलिए कानूनी जवाबदेही पर बहस छिड़ जाती है। विपक्षी दलों ने उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं।

(ii) यह AI नियुक्ति व्यापक रामा IV सरकार का हिस्सा है, जो 12 सितंबर 2025 को शपथ लेगी, जिसमें अल्बाना कोकिउ (आंतरिक), एलिसा स्पिरोपाली (विदेश मामले) और एविस साला (स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण) जैसे प्रमुख मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे।

(iii) राष्ट्रपति बजरम बेगज ने कैबिनेट में बदलावों को

मंजूरी दे दी, जो एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें AI को प्रतीकात्मक लेकिन कार्यात्मक मंत्री की भूमिका मिली है, जिससे अल्बानिया को AI-संचालित शासन में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थान मिला है।

2. भारतीय तटरक्षक बल ने रोम, इटली में चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन (CGGS) में भाग लिया।

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 11-12 सितंबर 2025 को रोम, इटली में आयोजित चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन (CGGS) में भाग लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में वैश्विक समुद्री शासन, सहयोग और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

• चौथे CGGS की सह-अध्यक्षता इटली और जापान ने की और इसमें 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया, जिससे यह समुद्री कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए सबसे बड़े वैश्विक मंचों में से एक बन गया।

• शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री दुर्घटनाओं और समग्र समुद्री सुरक्षा ढाँचों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया (ER) में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Key Points:-

(i) भारत का प्रतिनिधित्व महानिदेशक (DG) परमेश शिवमणि के नेतृत्व में दो सदस्यीय ICG प्रतिनिधिमंडल ने किया, जिसने बहुपक्षीय समुद्री सहयोग में भारत की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला।

(ii) यह घोषणा की गई कि 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा 2027 में चेन्नई, तमिलनाडु में किया जाएगा, जो भारतीय तटरक्षक बल के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ होगा।

BANKING & FINANCE

1. नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल ऋण अवसंरचना (CDCI) शुरू करेगा।

सितंबर 2025 में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDCI) शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ऋण प्रसंस्करण को डिजिटल और स्वचालित करना, दक्षता बढ़ाना और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के खिलाफ RRB प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

• CDCI प्लेटफॉर्म को ऋण उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ऋण प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता में सुधार

लाने, तथा मैनुअल हस्तक्षेप और कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• भारत सरकार की 'एक राज्य - एक RRB' नीति के तहत, जो 1 मई 2025 से प्रभावी है, RRB की संख्या 43 से 28 तक समेकित की गई, जिनकी लगभग 92% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे व्यापक ग्रामीण पहुंच सुनिश्चित हुई।

Key Points:-

(i) NABARD CDCI के अंतर्गत नए ऋण उत्पादों को समर्थन देगा, जिसमें प्रथम-हानि डिफ़ॉल्ट गारंटी के साथ आवास ऋण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए अनुकूलित ऋण शामिल हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन और ऋण पहुंच का विस्तार होगा।

(ii) CDCI प्रणाली सभी एकीकृत RRB को एकल कोर बैंकिंग समाधान (CBS) में एकीकृत करेगी और तेजी से जोखिम मूल्यांकन और सूचित ऋण निर्णय लेने के लिए भूमि रिकॉर्ड, CIBIL (क्रेडिट सूचना ब्यूरो इंडिया लिमिटेड) और आधार के साथ जोड़ेगी, जिससे ग्रामीण बैंकिंग बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा।

MOUs and Agreement

1. NIFT पटना ने बिहार के वस्त्र क्षेत्र में जीविका SHG महिलाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार देने के लिए ABFRL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सितंबर 2025 में, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), पटना, बिहार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में, जीविका पहल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोज़गार के अवसर प्रदान करने हेतु आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (ABFRL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• यह समझौता ज्ञापन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों, जीविका दीदियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, ताकि उन्हें कपड़ा और परिधान क्षेत्र में उद्योग-संबंधित कौशल का प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका में सुधार लाया जा सके।

• NIFT पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिधान निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएँ और कपड़ा मशीनरी का संचालन शामिल होगा, जिससे महिलाओं को स्थायी रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

• यह पहल बिहार के बेगूसराय में ABFRL की आगामी विनिर्माण इकाई से सीधे जुड़ी हुई है, जहाँ प्रशिक्षित जीविका दीदियों को कपड़ा उत्पादन भूमिकाओं में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

Key Points:-

(i) जीविका कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा विश्व बैंक (WB) के सहयोग से 2006 में ग्रामीण गरीबी को कम करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

(ii) NIFT पटना और ABFRL के बीच सहयोग से कौशल विकास और निजी क्षेत्र के रोज़गार के बीच तालमेल मज़बूत होने की उम्मीद है, जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और बिहार की ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

सितंबर 2025 में, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJ) सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री (PM) के रूप में शपथ ली, जिससे वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन गईं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन 'शीतल निवास' में उन्हें शपथ दिलाई।

- **सुशीला कार्की की नियुक्ति भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनरल जेड के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई, जिसके कारण उनके पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।**
- **अंतरिम सरकार ने घोषणा की कि 5 मार्च 2026 को नए आम चुनाव होंगे।**
- **उनका न्यायिक करियर 32 वर्षों का रहा है। उन्होंने 1979 में विराटनगर में वकालत शुरू की और कोशी क्षेत्रीय बार एसोसिएशन तथा विराटनगर अपीलीय बार, दोनों की अध्यक्ष रहीं। 2009 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश और बाद में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।**

Key Points:-

(i) सुशीला कार्की ने इससे पहले 2016 और 2017 के बीच नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वह दो पुस्तकों की लेखिका भी हैं, 'न्याय', जो एक जीवनी संबंधी कृति है, और 'कारा', जो उनके न्यायिक और राजनीतिक अनुभवों से प्रेरित है।

(ii) उनके योगदान को 2004 में संभव कानून पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से मान्यता मिली है, जो नेपाल की न्यायिक प्रणाली को आगे बढ़ाने और न्याय, पारदर्शिता और कानूनी अखंडता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका का सम्मान करता है।

2. एल सत्य श्रीनिवास को एशियाई विकास बैंक (ADB) में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

14 सितंबर 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग (DoC) में विशेष सचिव एल सत्य श्रीनिवास को एशियाई विकास बैंक (ADB) में भारत के कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में नियुक्त करने को मंज़ूरी दे दी। वह विकास शील का स्थान लेंगे।

• 1991 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी एल सत्य श्रीनिवास 28 फरवरी 2026 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर कार्य करेंगे, और उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए या अगले आदेश तक अनुबंध के आधार पर कार्य करेंगे।

• उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ADB में इस उच्च-स्तरीय पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों का पारंपरिक प्रभुत्व टूट गया है, जो IRS कैडर से एक दुर्लभ प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

• इस भूमिका में, वह एडीबी निदेशक मंडल में न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश, भूटान, लाओस, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे बहुपक्षीय बैंक के भीतर क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा।

Key Points:-

(i) श्रीनिवास ने भारत की व्यापार कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वे यूरोपीय संघ (EU) के साथ ई-कॉमर्स व्यापार समझौते के लिए मुख्य वार्ताकार रहे हैं, और यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता का नेतृत्व किया है।

(ii) भारत ADB में एक प्रमुख हितधारक बना हुआ है, जो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक और सबसे बड़ा उधारकर्ता है। अप्रैल 2025 तक, ADB ने भारत को 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉवरेन ऋण और 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गैर-सॉवरेन निवेश देने की प्रतिबद्धता जताई है।

IMPORTANT DAYS

1. भारत ने 14 सितंबर, 2025 को 76वाँ हिंदी दिवस मनाया।

14 सितंबर 2025 को, भारत हिंदी दिवस मनाया, जो संविधान सभा द्वारा 1949 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के निर्णय की 76वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

• हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रस्तावित किया था, जबकि 1953 में, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर

को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो कि बेहर राजेंद्र सिंह की जयंती के साथ मेल खाता है।

• 2025 के समारोह के एक भाग के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

Key Points:-

(i) सम्मेलन के दौरान, अमित शाह ने हिंदी के प्रचार और प्रयोग में योगदान के लिए सरकारी अधिकारियों और संगठनों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और अन्य पुरस्कार प्रदान किए।

(ii) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MMA) ने आधिकारिक कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा समारोह (14-30 सितंबर 2025) का शुभारंभ किया।

DEFENCE

1. भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली नौसेना सुविधा चालू की।

सितंबर 2025 में, भारतीय नौसेना (IN) ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी नई तट-आधारित नौसैनिक सुविधा, भारतीय नौसेना पोत (INS) अरावली का जलावतरण किया। इस जलावतरण समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख (CNS) एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने की, जो समुद्री सुरक्षा और निगरानी में एक रणनीतिक कदम है।

• INS अरावली के कमीशनिंग समारोह में CNS के लिए 50 जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, कैप्टन सचिन कुमार सिंह द्वारा संस्कृत में मंगलाचरण किया गया, नौसेना पत्नी कल्याण संघ (NWWA) की अध्यक्ष शशि त्रिपाठी द्वारा कमीशनिंग पट्टिका का अनावरण किया गया, तथा राष्ट्रगान के साथ नौसेना ध्वज का औपचारिक रूप से ध्वजारोहण किया गया।

• INS अरावली का नाम गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला से लिया गया है, जो धीरज, सतर्कता और लचीलेपन का प्रतीक है। यह बेस भारतीय नौसेना के समुद्री सुरक्षा के मिशन को दर्शाता है और शक्ति एवं तकनीकी प्रगति पर उसके ज़ोर को दर्शाता है।

• कैप्टन सचिन कुमार सिंह को INS अरावली का पहला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह बेस गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (IMAC) और सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा, जिससे भारत की समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) में वृद्धि होगी।

Key Points:-

(i) इस सुविधा को संचार और सूचना प्रबंधन, कमांड-एंड-कंट्रोल नेटवर्क को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में वास्तविक समय समुद्री खतरे के आकलन को सक्षम करने के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

(ii) इसका आदर्श वाक्य, 'सामुद्रिक सुरक्षायः सहयोग' (सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा), प्रौद्योगिकी के

माध्यम से सहकारी सुरक्षा को मजबूत करता है।

(iii) INS अरावली भारत के महासागर विजन (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) का प्रतीक है। एक सहयोगी केंद्र के रूप में कार्य करते हुए, यह नौसैनिक प्लेटफार्मों और साझेदारियों को एकीकृत करता है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में 'पसंदीदा सुरक्षा साझेदार' के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत होती है।

2. भारतीय नौसेना ने GRSE द्वारा निर्मित दूसरा स्वदेशी ASW उथले पानी का जहाज 'एंड्रोथ' को शामिल किया।

13 सितंबर 2025 को, भारतीय नौसेना (IN) ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) में से दूसरे "एंड्रोथ" को शामिल किया, जिससे भारत की तटीय रक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूती मिली।

• इस युद्धपोत का नाम लक्षद्वीप द्वीपसमूह के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो भारत के अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारतीय नौवहन रजिस्टर (IRS) के नियमों के तहत डिज़ाइन किया गया यह पोत पनडुब्बी रोधी युद्ध, बारूदी सुरंग बिछाने और लंबी दूरी की तटीय निगरानी में सक्षम है।

• "एंड्रोथ" 77 मीटर लंबा, 10.5 मीटर चौड़ा, 900 टन विस्थापन वाला और 25 नॉट (46 किमी/घंटा) की गति तक पहुँचने में सक्षम है। 57 कर्मियों के दल द्वारा संचालित, यह डीजल इंजन-वॉटरजेट संयोजन से संचालित सबसे बड़े भारतीय नौसेना जहाजों में से एक है, जो उथले पानी में उच्च गतिशीलता प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) यह पोत हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी ASW रॉकेट, 76 मिमी मुख्य बंदूक और सतह और हवाई दोनों खतरों से निपटने के लिए क्लोज-इन हथियार प्रणालियों (CIWS) से लैस है, जिससे यह भारत के नौसैनिक शस्त्रागार में एक शक्तिशाली वृद्धि है।

(ii) यह पनडुब्बी का पता लगाने के लिए उन्नत उथले पानी सोनार प्रणालियों और आधुनिक नेविगेशन और निगरानी रडार से लैस है, जो हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाता है।

(iii) 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, "एंड्रोथ" भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत (स्व-विश्वसनीय भारत) दृष्टिकोण के अनुरूप है। 2019 में रक्षा मंत्रालय (MoD) की मंजूरी के तहत 16 ASW-SWC को मंजूरी दी गई, जिनमें से 8 का निर्माण GRSE द्वारा और 8 का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा पुराने अभय-श्रेणी के कोरवेट की जगह लिया जाएगा।

BOOKS & AUTHORS

1. सितंबर 2025 में उनकी जन्म शताब्दी पर "एम. एस. स्वामीनाथन: द मैन हू फेड इंडिया" जीवनी का विमोचन किया गया।

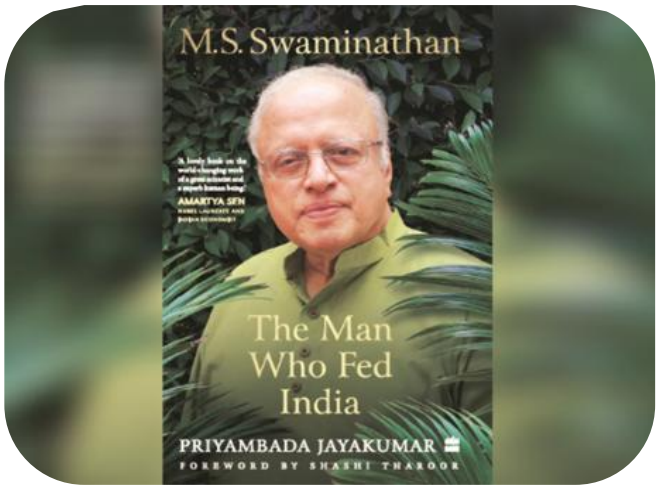

सितंबर 2025 में, प्रियंबदा जयकुमार द्वारा लिखित जीवनी "एम. एस. स्वामीनाथन: द मैन हू फेड इंडिया", 7 अगस्त 1925 को जन्मे मोनकोम्बु संबाशिव (एम. एस.) स्वामीनाथन की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाशित की गई। हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक कृषि और भारत की हरित क्रांति में उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डालती है।

- **यह जीवनी स्वामीनाथन के कुंभकोणम, तमिलनाडु से एक वैश्विक नेता बनने तक के सफर का वर्णन करती है, जिन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से भारत की हरित क्रांति का मार्गदर्शन किया।**

- **एम. एस. स्वामीनाथन को गेहूँ और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश करने के लिए "हरित क्रांति का जनक" माना जाता है, जिसने भारत के खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया।**

- **एक वैज्ञानिक होने के अलावा, उन्हें एक संरक्षणवादी, नारीवादी, गांधीवादी, संस्था निर्माता, राजनयिक और दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता था, जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है।**

Key Points:-

(i) स्वामीनाथन को कई पुरस्कार मिले, जिनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1971), प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार (1987) और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न (2024) शामिल हैं।

(ii) उनके राष्ट्रीय सम्मानों में पद्म श्री (1967), पद्म भूषण (1972) और पद्म विभूषण (1989) शामिल हैं, जो विज्ञान, कृषि और समाज के प्रति उनकी आजीवन सेवा को मान्यता देते हैं।

OBITUARY

1. मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी.डी. लापांग का 93 वर्ष की आयु में शिलांग में निधन हो गया।

सितंबर 2025 में, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री (CM), डोनवा डेथवेल्सन (डी.डी.) लापांग, जिन्हें 'माहे' के नाम से भी जाना जाता था, का 93 वर्ष की आयु में शिलांग में निधन हो गया। 10 अप्रैल 1932 को जन्मे, वे 1992 से 2010 के बीच पाँच बार मुख्यमंत्री रहे।

- **डी.डी. लपांग ने अपना करियर नोंगपोह के साल्डेन बेसिक स्कूल में शिक्षक के रूप में शुरू किया और बाद में राजनीति में आने से पहले असम वन विभाग और स्कूलों के उप-निरीक्षक के रूप में सेवा की। उनकी राजनीतिक यात्रा मेघालय के लिए दशकों की सेवा को दर्शाती है।**

- **उन्होंने 1972 में नोंगपोह निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और विधानसभा सदस्य (MLA) बने। समय के साथ, उन्होंने गृह, वित्त और शिक्षा जैसे कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाला और मेघालय प्रदेश कांग्रेस**

समिति (MPCC) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

Key Points:-

(i) 1992 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल होने के बाद, लपांग पहली बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने। वे 2003, 2007, 2009 और 2010 में भी मुख्यमंत्री रहे, हालाँकि उनके कार्यकाल में अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और INC के नेतृत्व वाली सरकार के भीतर गठबंधन की चुनौतियाँ रहीं।

(ii) 2018 में, वरिष्ठ नेताओं को सेवानिवृत्त करने की नीति का हवाला देते हुए, लापांग ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बाद में कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) में शामिल हो गए। वे हाल तक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 2024 तक मेघालय सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे।

(iii) मेघालय के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक के रूप में याद किए जाने वाले लापांग की राजनीतिक विरासत पांच दशकों से अधिक समय तक फैली हुई है, जिसने उन्हें राज्य के शासन और नेतृत्व के इतिहास को आकार देने में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया है।

Static GK

Mizoram	मुख्यमंत्री (CM) : पु लालदुहोमा	राज्यपाल-जनरल (सेवानिवृत्त): डॉ. विजय कुमार (वी.के.) सिंह
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
Manipur	राजधानी: इम्फाल	राज्यपाल: अजय कुमार भल्ला
MoD	मंत्री: राजनाथ सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Albania	प्रधानमंत्री: एडी रामा	राजधानी: तिराना
NABARD	स्थापना : 1982	मुख्यालय: मुंबई
Nepal	राजधानी: काठमांडू	मुद्रा: नेपाली रुपया
Asian Development Bank (ADB)	अध्यक्ष : मसातो कांडा	मुख्यालय : मेट्रो मनीला, फिलीपींस
Indian Navy (IN)	नौसेना प्रमुख (CNS) : एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : कमोडोर पीआर हरि	मुख्यालय : कोलकाता, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल)
Meghalaya	मुख्यमंत्री (CM) : कॉनराड कोंगकल संगमा	राज्यपाल - सीएच विजयशंकर